कानपुर, मंगलवार, 06 जनवरी, 2026 प्रधान संपादकः पुरुषोत्तम द्विवेदी
वर्षः 03, अंकः 10, पृष्ठः 8+4

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

www.swarajindianews.com
swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

इनसाइड लेबनान पर फिर इस्राइल का हवाई हमला >Pg12

रेलवन एप से मिलेगा 3% का फायदा > Pg03

मूल्यः 2 ₹

इंदौर में दूषित पानी कांड पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त

मुख्य सचिव अदालत में हाजिर हों...

- भागीरथपुरा मौत मामले में 15 जनवरी को मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से तलब
- मौतों के आंकड़ों में विरोधाभास पर कोर्ट नाराज़, सरकार को लगाई फटकार

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

इंदौर। भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी पीने से हुई मौतों और सैकड़ों लोगों के बीमार होने के मामले को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अत्यंत गंभीर मानते हुए सख्त रुख अपनाया है। इस प्रकरण से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।

मंगलवार को इंदौर हाईकोर्ट में एक साथ तीन से चार जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इन याचिकाओं में भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की आपूर्ति से हुई मौतों और बड़े पैमाने पर लोगों के बीमार होने को लेकर प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और याचिकाकर्ता एडवोकेट रितेश ईरानी ने बताया कि कोर्ट ने माना है कि इतने संवेदनशील और गंभीर मामले में शीर्ष स्तर पर जवाबदेही तय होना जरूरी है, इसलिए मुख्य सचिव को तलब किया गया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। न्यायालय ने कहा कि मौतों के आंकड़ों को लेकर प्रशासन की रिपोर्ट में विरोधाभास सामने आ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। पहले सरकार की ओर से चार मौतों की जानकारी दी गई थी, जबकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक बताई जा रही है।

यह जनहित याचिकाएं एडवोकेट रितेश ईरानी, पूर्व पार्षद महेश गर्ग और प्रमोद द्विवेदी द्वारा एडवोकेट मनीष यादव के माध्यम से दायर की गई हैं। इससे पहले 2 जनवरी को हुई सुनवाई में भी सरकार ने चार मौतों का जिक्र किया था, लेकिन उस समय भी मृतकों की संख्या ज्यादा होने की बात सामने आई थी, जो अब और बढ़ गई है। मामले की सुनवाई जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की नियमित खंडपीठ में हुई। कोर्ट ने देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर में इस तरह की घटना पर हैरानी जताते हुए कहा कि यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का संकेत है।

कंबल से इस तरह बनाई गई रस्सी

जिला जेल से दो बंदी फरार

जेलर-डिप्टी जेलर समेत पांच सस्पेंड

- नए साल के जश्न के दौरान कंबलों की रस्सी बनाकर दीवार फांदी, बंदियों की तलाश में टीमें गठित

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कन्नौज। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के अनौगी स्थित जिला जेल में रविवार रात जब जेल प्रशासन और सुरक्षाकर्मी नए साल के जश्न में व्यस्त थे, उसी दौरान दो बंदी कंबलों को बांधकर रस्सी बनाते हुए जेल की ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। पूरी रात जेल प्रशासन को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। लापरवाही सामने आने पर जेलर विनय प्रताप सिंह, डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद, जेलवार्डर शिवेंद्र सिंह यादव, अतुल मिश्रा और नवीन कुमार को निलंबित कर दिया गया है।

सोमवार सुबह नियमित गिनती के दौरान दो बंदियों के न मिलने पर हड़कंप मच गया। पहले जेल प्रशासन ने मामले को दबाने और खोजबीन करने की कोशिश की, लेकिन जेल की दीवार पर लटके कंबल मिलने के बाद सच्चाई सामने आ गई। इसके बाद उच्चाधिकारियों को सूचना दी गई। जेल सूत्रों के अनुसार फरार बंदियों में अंकित निवासी हजरापुर थाना तालग्राम और डम्पी उर्फ शिवा निवासी मलगवा थाना ठठिया शामिल है।

घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री और पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मौके पर पहुंचे। देर शाम डीआईजी जेल प्रदीप गुप्ता ने भी जिला जेल पहुंचकर जांच की। प्रारंभिक जांच में गंभीर लापरवाही सामने आने पर जेलर विनय प्रताप सिंह, डिप्टी जेलर बद्री प्रसाद, जेलवार्डर शिवेंद्र सिंह यादव, अतुल मिश्रा और नवीन कुमार को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने मामले की रिपोर्ट शासन को भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं, फरार बंदियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और प्रशासन की कई टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है।

बांदा में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में फास्टट्रैक कोर्ट ने आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह मामला कालिंजर थाना क्षेत्र का है।

- कालिंजर थाना क्षेत्र की घटना, फास्टट्रैक कोर्ट ने 56 दिन में सुनाया फैसला

अभियोजन के अनुसार, 25 जुलाई को घटित घटना के बाद पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पीड़िता की पहचान गोपनीय रखते हुए चिकित्सकीय परीक्षण, गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 7 अक्टूबर को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। फास्टट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि अपराध की प्रकृति अत्यंत गंभीर है और समाज पर इसके व्यापक दुष्प्रभाव को देखते हुए कानून के तहत कठोरतम दंड आवश्यक है।

घोटाले के खेल अब हमेशा के लिए बंद हो गए : योगी

- जी राम जी अधिनियम का सीएम योगी ने किया स्वागत, 125 दिन रोजगार और साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विकसित भारत जी राम जी अधिनियम का स्वागत करते हुए इसे ग्रामीण विकास और स्थायी रोजगार सृजन की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। मंगलवार को लोकभवन में आयोजित एनडीए सरकार की पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अधिनियम गांव, गरीब और श्रमिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला साबित होगा।

सीएम योगी ने बताया कि जी राम जी योजना के तहत अब रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। इसके साथ ही मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक आधार पर होगा और यदि भुगतान में देरी होती है तो श्रमिकों को ब्याज सहित राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था श्रमिकों के सम्मान और अधिकारों को मजबूत करने वाली है।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन लोगों ने देश को वर्षों तक गरीबी के दंश में झोंक दिया, वही आज गरीबों और गांवों के हित में उठाए गए कदमों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत की आधारशिला तभी रखी जा सकती है, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।

सीएम योगी ने कहा कि जी राम जी योजना के तहत अब ऑनलाइन हाजिरी, डीबीटी के माध्यम से भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था लागू की गई है, जिससे फर्जी नामों पर भुगतान और घोटालों की गुंजाइश समाप्त हो गई है। उन्होंने सपा शासनकाल का जिक्र करते हुए सोनभद्र में मनरेगा घोटाले की याद दिलाई और कहा कि अब ऐसे खेल हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मंत्री ओमप्रकाश राजभर, संजय निषाद, आशीष पटेल, अनिल कुमार और रालोद नेता राजपाल बालियान भी मौजूद रहे।

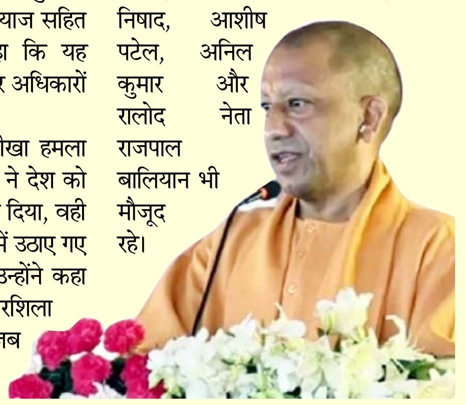

दूषित पेयजल आपूर्ति रोकने को लेकर कर्मचारी संघ ने उठाई आवाज

इंदौर में हुई घटना के बाद हेल्प-डेस्क और नोडल अधिकारी नियुक्त करने की मांग

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। देश-प्रदेश एवं कर्मचारी हितों के लिए कार्यरत एक संगठन ने शहर में स्वच्छ पेयजल व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई है। संगठन ने हाल ही में मध्य प्रदेश के इन्दौर जिले में दूषित पेयजल आपूर्ति से बड़ी संख्या में नागरिकों के बीमार होने की घटना को अत्यंत दुःखद बताते हुए कहा कि ऐसी स्थिति कानपुर जैसे बड़े महानगर में उत्पन्न न हो, इसके लिए समय रहते ठोस कदम उठाए जाने आवश्यक हैं।

संगठन की ओर से बताया गया कि इन्दौर जैसे शहर, जिसे स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वहां जल आपूर्ति से उल्टी, दस्त सहित अन्य बीमारियों के कारण बड़ी संख्या में लोग अस्पतालों में भर्ती हुए।

संगठन ने दूषित पानी से प्रभावित नागरिकों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।

इसी क्रम में नगर निगम जलकल चालक संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने मांग की है कि कानपुर नगर में संभावित दूषित जल आपूर्ति की रोकथाम के लिए एक विशेष हेल्प-डेस्क तथा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, ताकि नागरिकों की शिकायतों का त्वरित संज्ञान लेकर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। कहा कि शहर की सीमाएं लगातार बढ़ रही हैं, रिहायशी क्षेत्रों में पम्पिंग स्टेशनों के माध्यम से जल आपूर्ति हो रही है, जबकि बाहरी क्षेत्रों एवं बस्तियों में निर्मित टंकियों से पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिनकी कई वर्षों से सफाई नहीं कराई गई है। इसके साथ ही एटीएम वाटर की भी लगभग पांच वर्षों से किसी विभाग द्वारा जांच नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया।

संगठन के प्रतिनिधियों ने नव वर्ष के अवसर पर महाप्रबंधक से भेंट कर पुष्प भेंट किए और ज्ञापन सौंपते हुए हेल्प-डेस्क के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन जारी करने का अनुरोध किया। ज्ञापन में यह भी प्रस्ताव रखा गया कि शिकायतकर्ता दूषित पानी की पांच सौ मिलीलीटर मात्रा, आधार कार्ड की छायाप्रति तथा जलकल विभाग को दिए गए जलकर की रसीद के साथ मुख्यालय स्थित हेल्प-डेस्क में शिकायत दर्ज कराएं, जिससे यदि कहीं दूषित जल आपूर्ति हो रही हो तो उसका तत्काल निस्तारण कराया जा सके।

संगठन ने दैनिक समाचार पत्रों से इस विषय को प्रमुखता से प्रकाशित कर नागरिकों को जागरूक करने का आग्रह किया है। ज्ञापन कार्यक्रम में अखिलेश सिंह, बजरंगी लाल यादव, मनोज कुमार, सानू अहमद, विक्की, मुन्ना, सलीम, जगदीश सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी एवं श्रमिक उपस्थित रहे।

श्रीअन्न का महत्व व उपयोग बताया,किसानों को दिया गया प्रशिक्षण

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर में हुआ आयोजन

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर के प्रसार निदेशालय स्थित लाल बहादुर शास्त्री सभागार में श्रीअन्न (मिलेट्स) वैज्ञानिक खेती से मूल्य वर्धन तक विषय पर एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम निदेशक शोध आरके यादव के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निदेशक शोध आरके यादव ने बताया कि मोटे अनाज गेहूं और चावल की तुलना में सस्ते होने के साथ-साथ उच्च प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और आयरन से भरपूर होते हैं। इनमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जिससे यह पोषण की दृष्टि से उपयोगी आहार हैं।

मुख्य अतिथि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी के निदेशक शोध एसके चतुर्वेदी ने ग्रामीण स्तर पर कुपोषण कम करने और पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए मिलेट्स एवं स्थानीय उत्पादों के पौष्टिक गुणों तथा उनकी प्रसंस्करण तकनीकों की विस्तृत जानकारी दी। विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक परमेंद्र सिंह ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने के लिए भारत के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज के सेवन से मधुमेह और मोटापे जैसी स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने में मदद मिलती है।

कार्यक्रम में विजय रत्ना तोमर ने बताया कि आर्थिक दृष्टि से मोटे अनाज अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि इनके उत्पादन में कम निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे ये किसानों के लिए आय का स्थायी स्रोत बन सकते हैं।

कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल सचिव नौशाद खान, निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र विजय कुमार यादव, कृषक समिति अध्यक्ष बाबू सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने किसानों को संबोधित किया। कार्यक्रम का संबोधन आयोजक सचिव श्वेता यादव द्वारा किया गया। आसपास के जनपदों से आए कृषकों ने कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी की।

प्रशिक्षण के दौरान कृषकों को पौष्टिक एवं स्वादिष्ट प्रसंस्करित उत्पादों के निर्माण में साफ-सुथरे और उपयोगी उपकरणों के प्रयोग, श्रीअन्न की वैज्ञानिक खेती, मूल्य वर्धन तथा उत्पादों के ठंडे, सूखे एवं हवादार स्थान पर संग्रहण जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं।

कार्यक्रम में महक सिंह, एमजेड सिद्दीकी, लोकेंद्र सिंह, वीके कनौजिया, विनोद प्रकाश, भूपेंद्र कुमार सिंह, मीडिया प्रभारी खलील खान ने उपस्थित होकर सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन अरविंद कुमार द्वारा किया गया।

प्रभारी मंत्री और जिलाध्यक्ष के सामने दोनों गुटों के पार्षदों की होगी पेशी

»स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। नगर निगम में निष्कासित पार्षदों और महापौर के पुत्र को लेकर चल रहे मामले का पटाक्षेप करने से पहले एक बार फिर से मंगलवार को दोनों पक्षों के पार्षदों से भाजपा जिलाध्यक्ष व क्षेत्रीय अध्यक्ष पूछताछ करेंगे। इसके बाद प्रभारी मंत्री के सामने महापौर प्रमिला पांडेय की उपस्थिति में फाइनल टेबल पर बात होगी। इसे लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष ने पूरे मामले पर दिन भर मंथन किया।

माना जा रहा है कि निष्कासित पार्षदों की निगम में वापसी के साथ उन्हें संगठन की ओर से चेतावनी भी दी जा सकती है। साथ ही निष्कासित पार्षदों के अपने क्षेत्रों में निगम की ओर से बजट नहीं देने वाली बात की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। यदि यह आरोप सही निकलेगा तो संगठन इसे गंभीरता से भी ले सकता है। पता चला है कि सोमवार को इस प्रकरण में पार्टी के उत्तर इकाई जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित और क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने मंथन किया है। इसी कड़ी में छह जनवरी को सुबह 11 बजे निष्कासित और उनके साथ वाले सभी छह पार्षदों को भाजपा उत्तर जिला कार्यालय नवीन मार्केट में बुलाया गया है। यहां पर जिलाध्यक्ष इन सभी से एक-एक कर बात करेंगे। दोपहर बाद प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के महानगर आगमन पर देर शाम सर्किट हाउस में दोनों पक्षों के पार्षदों को बुलाकर बातें सुनी जाएंगी।बताया जा रहा है कि महापौर को भी मौजूद रहने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि सभी पहलुओं पर विचार करते हुए संगठन में संतुलन पर जोर दिया जाएगा।

रेलवन एप: अनारक्षित टिकट पर सभी डिजिटल भुगतान पर मिलेगा 3% का फायदा

यह सुविधा प्रायोगिक तौर पर 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू रहेगी

स्वराज इंडिया न्यूज

कानपुर । रेलवे यात्रियों को डिजिटल सुविधाओं से जोड़ने और कैशलेस लेन-देन को बढ़ावा देने की दिशा में एक और अहम कदम उठाया गया है। रेलवे द्वारा संचालित रेलवन एप के माध्यम से अनारक्षित रेल टिकट खरीदने पर अब सभी डिजिटल भुगतान माध्यमों से 3 प्रतिशत का लाभ मिलेगा। यह सुविधा प्रायोगिक तौर पर 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक लागू रहेगी।

अब तक रेलवन एप पर अनारक्षित टिकट बुक करने पर केवल आर-वॉलेट से भुगतान करने पर ही 3 प्रतिशत बोनस कैशबैक की सुविधा मिलती थी, लेकिन यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने इसे सभी डिजिटल पेमेंट मोड तक विस्तारित कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सहित अन्य स्वीकृत डिजिटल माध्यमों से भुगतान करने पर यात्रियों को टिकट मूल्य पर 3 प्रतिशत की सीधी बचत होगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती देने के साथ यात्रियों को नकद रहित लेन-देन के लिए प्रेरित करेगा। विशेष रूप से दैनिक यात्रा करने वाले यात्रियों, उपनगरीय क्षेत्रों में सफर करने वालों और अनारक्षित श्रेणी के यात्रियों को इस सुविधा से प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।सीआरआईएस द्वारा विकसित एकीकृत सुपर ऐप रेलवन का बीटा संस्करण जनवरी 2025 में शुरू किया गया था।

इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रेल कनेक्ट या यूटीएस मोबाइल ऐप के मौजूदा उपयोगकर्ता सीधे लॉगिन कर सकते हैं। रेलवन ऐप पर अनारक्षित व आरक्षित टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन व स्टेशन से जुड़ी जानकारियां, शिकायत निवारण और अन्य यात्री सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हैं।रेलवन ऐप पहले से ही अनारक्षित टिकट के लिए काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों से यात्रियों को राहत दिला रहा है। यह पहल न केवल यात्रियों के समय और धन की बचत करेगी, बल्कि रेलवे सेवाओं को और अधिक आधुनिक, सुगम व पर्यावरण अनुकूल बनाने में भी सहायक सिद्ध होगी।

डीसीएम-ट्रक आमने सामने भिड़े, ड्राइवर की मौत

हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर नगर। घाटमपुर के बरनाव मोड़ पर कोहरे के चलते मंगलवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक व डीसीएम में आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में डीसीएम चालक की मौके पर मौत हो गयी। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे करवाकर यातायात बहाल कराया है। इस दौरान लगभग आधा घंटे यातायात प्रभावित रहा।

घाटमपुर थाना क्षेत्र के पतारा कस्बा निवासी 38 वर्षीय दिनेश कुमार डीसीएम लेकर घाटमपुर की ओर से कानपुर जा रहा था। बरनाव मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक से

घाटमपुर में सुबह हुए हादसे से हाईवे पर प्रभावित रहा यातायात

आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी, कि गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। हादसे में डीसीएम चालक दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया, वही ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से भाग निकला। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को पतारा सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने दिनेश को मृत घोषित कर दिया। घाटमपुर इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट ने बताया कि तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद कानपुर सागर हाइवे पर यातायात प्रभावित हो गया। पुलिस ने एनएचआई की के क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे करवाकर हाइवे पर यातायात बहाल कराया गया है।

मृतक की फाइल फोटो

बिटकॉइन के नाम पर 2 करोड़ ठगे मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार

प्रमुख संवाददाता/स्वराज इंडिया

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिटकॉइन में निवेश और मोटे मुनाफे का झांसा देकर दो करोड़ रुपये की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। चकेरी क्षेत्र में मेडिकल स्टोर चलाने वाले आदित्य सिंह ने खुद को क्रिप्टोकरेंसी में बड़ा निवेशक बताते हुए पड़ोसी समेत चार लोगों से यह रकम ऐंठ ली। पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि उसके एक अन्य साथी की तलाश जारी है।

पीड़ित उमाशंकर के अनुसार, पड़ोसी होने के चलते उनकी आदित्य सिंह से अच्छी जान-पहचान थी। आरोपी ने खुद को हिमाचल प्रदेश में एलोपैथिक दवाओं की दो फैक्ट्रियों का मालिक बताया और दावा किया कि उसने करीब 20 साल पहले बिटकॉइन में निवेश किया था, जिसकी कीमत अब 44 करोड़ रुपये हो चुकी है। उसने यह भी कहा कि आरबीआई ने नियमों के चलते यह रकम फ्रीज कर रखी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिलीज कराया जाना है।

फर्जी दस्तावेज दिखाकर...

आदित्य ने भरोसा दिलाने के लिए खुद को पीएमओ में तैनात अधिकारी का दोस्त बताया और अपने ही एक साथी से फोन पर बातचीत कराकर पीड़ितों को विश्वास में लिया। इसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, आरबीआई से जुड़े पत्र, फर्म रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड और जीएसटी जैसे फर्जी दस्तावेज दिखाकर निवेश के लिए तैयार कर लिया। आरोपी ने एसएसआरए ग्रुप के नाम से एक फर्जी फर्म बनवाकर अगस्त 2021 से नवंबर 2025 के बीच पीड़ितों से करीब दो करोड़ रुपये निवेश कराए। इसमें 1.25 करोड़ रुपये ऑनलाइन और 75 लाख रुपये नकद लिए गए। लालच में आए पीड़ितों ने प्लॉट और जेवर तक बेचकर पैसा लगाया, लेकिन न रकम रिलीज हुई और न ही कोई मुनाफा मिला। सच्चाई सामने आने पर पीड़ितों ने पुलिस से शिकायत की।

पीएमओ में दोस्त होने का दावा कर 44 करोड़ की फीज रकम रिलीज कराने का झांसा

आरोपी मेडिकल स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मामले में उसके उस साथी की तलाश की जा रही है, जिसे पीएमओ का अधिकारी बताकर फोन पर बात कराई जाती थी। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है।

- अजय कुमार मिश्र, थाना प्रभारी चकेरी

दिल्ली में दुष्कर्म केस का डर दिखाकर वसूली का आरोप

» पत्नी और उसके साथी पर फर्जी मुकदमों के जरिए ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज

» पति ने बेटे के भविष्य का हवाला देकर कोर्ट और पुलिस से लगाई गुहार

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी दिल्ली में दुष्कर्म के फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर लोगों से मोटी रकम की वसूली कर रही है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर वह दूसरों को भी झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देती है। पति की तहरीर पर पत्नी और उसके कथित साथी के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

पीड़ित युवक के मुताबिक उसकी शादी नवंबर 2007 में हुई थी। वर्ष 2011 में पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन कुछ समय बाद वह दिल्ली चली गई। आरोप है कि दिल्ली पहुंचकर उसने एक व्यक्ति के साथ मिलकर फर्जी कंपनी खोली और ठगी का धंधा शुरू कर दिया। युवक का दावा है कि उसकी पत्नी खुद को अविवाहित बताकर लोगों से नजदीकियां बढ़ाती है और बाद में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें ब्लैकमेल करती है।

युवक का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम से उसके बेटे का भविष्य खतरे में पड़ गया है। बेटे को अपने पास रखने के लिए उसने न्यायालय में वाद दाखिल किया, लेकिन आरोप है कि पत्नी ने फर्जी दस्तावेज लगाकर शपथपत्र में लखनऊ का गलत पता दर्ज करा दिया। पीड़ित ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल और पुलिस आयुक्त से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। न्याय न मिलने पर युवक ने अंततः कोर्ट का रुख किया, जिसके आदेश पर पत्नी और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्यवाहक थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों तक पहुंचाई मदद

झुग्गी झोपड़ी में जरूरतमंदों को कपड़े, टोपी, मोजे और दस्ताने वितरित, बच्चों को नोटबुक व पेन देकर बढ़ाया उत्साह

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। शीतकालीन मिशन दल ठंड के मौसम में गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए सहारा बनकर सामने आया है। दल के सदस्यों ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले निर्धनों को कपड़े भेंट किए और ठंड से बचाव के लिए टोपी, मोजे व दस्ताने वितरित किए। वहीं शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ने वाले बच्चों को नोटबुक और पेन देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और बालिकाओं की शिक्षा के लिए देश का पहला विद्यालय खोलने वाली माता सावित्रीबाई के जन्मदिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में दल ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षा ऐसा सशक्त माध्यम है, जिससे समाज की बुराइयों से लड़कर संस्कार, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक उत्थान की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

कार्यक्रम में दल के वरिष्ठ जन अपने बच्चों के साथ शामिल हुए। वरिष्ठ केंद्रीय अधिकारी शिवराम सिंह ने कहा कि बच्चों को लोकहित के कार्यों से रूबरू कराना आवश्यक है। केवल रोजगारपरक शिक्षा ही नहीं, बल्कि नैतिक मूल्य और मानवीयता से जुड़े कार्यक्रमों में सहभागिता बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। वरिष्ठ अधिकारी मिथलेश कनौजिया ने कहा कि सामाजिक कार्यों में बच्चों की सहभागिता उन्हें अनुभव देती है और समाज को समझने में मदद करती है, जिससे वे आगे चलकर अच्छे नागरिक बन सकें।

शीतकालीन मिशन कार्यक्रम में चिकित्सा स्नातक चतुर्थ वर्ष की छात्रा यशी और नवोद्यम क्षेत्र में कार्यरत अंकुर ने भी अपनी भागीदारी निभाई। शीतकालीन मिशन के मुख्य संयोजक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जाड़े के मौसम में जनहितकारी कार्यों के साथ बच्चों के समाजीकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। सह संयोजक अजय सिंह ने कहा कि बच्चों का समाजीकरण ही देश और समाज के विकास की मजबूत नींव है।

हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज में एएसडीडी सूची का प्रकाशन

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज चमनगंज परिसर में एएसडीडी सूची का प्रकाशन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी बूथ लेवल अधिकारियों द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों के नियुक्त बूथ लेवल एजेंटों को एएसडीडी सूची उपलब्ध कराई गई।

सूची प्रकाशन कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इनमें नदीम अहमद अधिवक्ता, मोहम्मद सलमान पार्षद प्रत्याशी, मोहसिन खान पार्षद प्रत्याशी, तकमील हसन खान, इम्तियाज अहमद, उज़ैर अहमद, मोहम्मद तालिब अधिवक्ता, इरशाद अहमद और अहमद तस्लीम प्रमुख रूप से शामिल रहे।

इसके अलावा गुलज़ार अहमद वरिष्ठ लिपिक हलीम मुस्लिम इंटर कॉलेज, मोहम्मद शोएब पर्यवेक्षक तथा नीतीश पर्यवेक्षक भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराया गया। प्रशासन की ओर से मतदाता सूची की पारदर्शिता और शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सम्पादकीय

अमेरिकी नियंत्रण की मंशा को ही दर्शाता

पिछले लंबे समय से डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी हमले के बाद गिरफ्तार करना निस्संदेह, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का घोर उल्लंघन है। एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण और उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाना अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी का दुर्लभ उदाहरण है। उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि सत्ता परिवर्तन होने तक वाशिंगटन इस लैटिन अमेरिकी देश का संचालन करेगा। यह एक खतरनाक परंपरा है, जिसकी पुनरावृत्ति अमेरिकी महाद्वीप से बाहर होने की आशंका भी बलवती हो सकती है। इसमें दो राय नहीं कि निकोलस मादुरो के पतन के बाद वेनेजुएला में मिश्रित प्रतिक्रिया होगी। अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से मादुरो को लगातार खलनायक बनाने की कोशिशें में एक वैश्विक तंत्र लगा हुआ था। वैसे आरोप मादुरो पर लगे कि उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया, असहमतियों को कुचला और लाखों लोगों को निर्वासन के लिये मजबूर किया। उन पर चुनाव में धांधली और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप भी लगते रहे हैं। लेकिन वैश्विक कूटनीति के जानकार मानते हैं कि ट्रंप के इस दांव का लक्ष्य तानाशाही के पीड़ितों को न्याय दिलाने या इस देश की संप्रभुता की रक्षा के बजाय वेनेजुएला के समृद्ध तेल भंडारों पर नियंत्रण हासिल करना ज्यादा रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका द्वारा सैन्य अभियान चलाकर देश से बाहर किसी शासनाध्यक्ष को गिरफ्तार करना तथा वहां की सत्ता को वाशिंगटन से संचालित करना निश्चय ही साम्राज्यवादी सोच का ही पर्याय है।

निस्संदेह, इस अमेरिकी निरंकुशता के गहरे भू-राजनीतिक परिणाम सामने आएंगे। यहां तक कि मादुरो का विरोध करने वाले अमेरिका के सहयोगी देश भी, अब मुखर होकर चेतावनी देने लगे हैं। रूस और चीन इस अमेरिकी कार्रवाई को नियम-कानून आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिये खतरा बता रहे हैं। वहीं वेनेजुएला के इस घटनाक्रम ने चीन को अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं पर अमेरिकी आलोचना को बेअसर करने का भरपूर मौका दे दिया है। जिससे ताइवान की चिंताएं बढ़ सकती हैं। अमेरिका के इस कृत्य ने इराक और अफगानिस्तान में हमले व सेना की तैनाती की यादें ताजा कर दी हैं। ऐसे युद्ध जो अमेरिकी आत्ममुग्धता और अति-आत्मविश्वास से शुरू हुए, लेकिन उनका समापन अपमानजनक विदाई से हुआ। लेकिन इन हमलों के बाद वे देश कभी सामान्य नहीं रह पाए। वहीं ट्रंप की यह दलील कि मादुरो को पकड़ने के लिये चलाए अभियान का खर्च वेनेजुएला के तेल राजस्व से वसूला जाएगा, उसके प्राकृतिक संसाधनों पर अमेरिकी नियंत्रण की मंशा को ही दर्शाता है। वहीं अमेरिका ने यह स्पष्ट नहीं किया कि सुशासन, सुरक्षा के लिये वेनेजुएला की जनता की आकांक्षाओं वाले किस नेता को सत्ता हस्तांतरण किया जाएगा। भारत भी उन देशों में शामिल है, जिन्होंने घटनाक्रम पर चिंता व्यक्त की है। । बहरहाल, देर-सवेर ट्रंप को अहसास होगा कि एक निरंकुश शासक को हटाना आसान है, लेकिन उस देश में दीर्घकालिक शांति-स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये गंभीर प्रयासों की जरूरत होती है।वहीं दूसरी ओर अमेरिका द्वारा सैन्य अभियान चलाकर देश से बाहर किसी शासनाध्यक्ष को गिरफ्तार करना तथा वहां की सत्ता को वाशिंगटन से संचालित करना निश्चय ही साम्राज्यवादी सोच का ही पर्याय है।

राष्ट्रीय- शिक्षा नीति 2020- भाषाई अस्मिता का नया क्षितिज

प्रो. दिनेश चन्द्रराय

कुलपति, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार।

भारत की भाषाई विविधता कभी भी केवल संवाद का जरिया नहीं रही, बल्कि यह उस सभ्यतागत चेतना का विस्तार है जिसने हज़ारों वर्षों से इस उपमहाद्वीप को एक सूत्र में पिरोए रखा है। अक्सर यह कहा जाता है कि भारत में हर कोस पर पानी और चार कोस पर वाणी बदल जाती है, लेकिन इस बदलाव के भीतर जो अंतर्धारा बहती है, वह एकता की है। आज जब हम 2026 के मुहाने पर खड़े होकर अपनी भाषाई विरासत को देखते हैं, तो स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (ह्श्वक्क) 2020 ने उस औपनिवेशिक हीनभावना को तोड़ने का साहस दिखाया है जिसने दशकों से हमारी मातृभाषाओं को दोयम दर्जे पर धकेल रखा था। भारत के भाषाई परिदृश्य में आए इस बदलाव को केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि उस नई पीढ़ी के आत्मविश्वास से समझा जा सकता है जो अब अपनी भाषा में रॉकेट साइंस समझने का सपना देख रही है।

जनसांख्यिकीय दृष्टि से देखें तो भारत की भाषाई विविधता दुनिया में सबसे अनूठा है। 2024-25 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, हिंदी बोलने वालों की संख्या जहाँ 60 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, वहीं बंगाली, मराठी, तेलुगु और तमिल जैसी भाषाएं वैश्विक मंच पर अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। यह महज संयोग नहीं है कि अलग-अलग भाषा परिवारों से होने के बावजूद भारतीय भाषाओं का व्याकरणिक ढांचा और उनकी अभिव्यक्ति का ढंग एक जैसा है। चाहे वह वाक्य में क्रिया का अंत में आना हो या फिर ध्वनियों का विशिष्ट उच्चारण, कश्मीरी से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही भाषाई चेतना प्रवाहित होती है। इसी चेतना को नई शिक्षा नीति ने अपना मुख्य आधार बनाया है। नीति का यह तर्क पूरी तरह वैज्ञानिक है कि एक बच्चा अपनी मातृभाषा में अवधारणाओं को जितनी गहराई और स्पष्टता से समझ सकता है, वह किसी विदेशी भाषा में संभव नहीं है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की अनिवार्यता ने न केवल शिक्षा के लोकतंत्रीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है, बल्कि उन करोड़ों ग्रामीण प्रतिभाओं के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं जो केवल भाषा की बाधा के कारण पीछे छूट जाती थीं।

शिक्षा नीति का सबसे दूरगामी और सकारात्मक प्रभाव उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। दशकों तक यह माना जाता रहा कि चिकित्सा और इंजीनियरिंग जैसी जटिल पढ़ाई केवल अंग्रेजी में ही संभव है, लेकिन आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दक्षिण के राज्यों में भारतीय भाषाओं में शुरू हुए तकनीकी पाठ्यक्रम इस मिथक को ध्वस्त कर रहे हैं। जब एक छात्र अपनी मूल भाषा में शरीर विज्ञान या? टेक्नोलॉजी को पढ़ता है, तो उसकी मौलिक सोच का विस्तार होता है। यह भाषाई पुनर्जागरण का ही परिणाम है कि अब ज्ञान का सृजन केवल अनुवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय भाषाओं में मौलिक शोध को बढ़ावा मिल रहा है। इसके साथ ही, त्रि-भाषा सूत्र में आए लचीलेपन ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नए सेतु निर्मित किए हैं। जब उत्तर भारत का कोई युवा तमिल या कन्नड़ सीखता है और दक्षिण का छात्र हिंदी या बांग्ला के साहित्य से जुड़ता है, तो वह एक भारत-श्रेष्ठ भारत के उस संकल्प को चरितार्थ करता है जो केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक और भाषाई है।तकनीक और डिजिटल क्रांति ने इस भाषाई महासूत्र को और अधिक सशक्त बना दिया है। केंद्र सरकार का भाषिणी मिशन और एआई-आधारित अनुवाद उपकरण आज उस दूरी को पाट रहे हैं जो सदियों से बनी हुई थी। आज एक किसान अपनी स्थानीय बोली में बोलकर इंटरनेट से संवाद कर सकता है संस्कृत और तमिल जैसी प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं को मुख्यधारा की शिक्षा और तकनीक से जोड़ना इस नीति की एक और बड़ी उपलब्धि है, जिसने हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान को आधुनिक नवाचारों के साथ संतुलित किया है।

भारतीय भाषाओं का यह नया युग केवल अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि एक राष्ट्र के आत्मविश्वास की वापसी है। नई शिक्षा नीति ने भाषाओं को केवल संवाद का माध्यम मानने के बजाय उन्हें पहचान और विकास का गौरव बनाया है। क्षेत्रीयता के छोटे विवादों से ऊपर उठकर, जब हम अपनी भाषाई विविधता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, तभी एक विकसित भारत की नींव मजबूत होती है। भाषाएं हमारी सभ्यता की धड़कनें हैं; यदि ये धड़कती रहेंगी, तो भारत की सांस्कृतिक अखंडता अक्षुण्ण रहेगी। आज की आवश्यकता इस भाषाई स्वाभिमान को बनाए रखने की है, क्योंकि अपनी भाषा को खोना केवल शब्दों को खोना नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से उखड़ जाना है।

अरावली की परिभाषा में निहित हो संरक्षण का लक्ष्य

पर्यावरण संकट

डा० सुधीर कुमार

अरावली पहाड़ियों के लिए कोई एक परिभाषा अपनाने और कानून बनाने से पहले सरकार और सुप्रीम कोर्ट को सभी कोणों से इसकी जांच करनी चाहिए। ऐसी परिभाषा न हो जो इन पर्वत शृंखलाओं को सीधे या अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचा सकती है। लक्ष्य संरक्षण हो न कि बाजारी ताकतों द्वारा अंधाधुंध दोहन। अरावली पहाड़ियां कभी अरबों साल पहले टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बनी ऊंचे वलित पहाड़ों की शृंखला थी जो लाखों साल की टूट-फूट और कटाव से घिसकर ऊंची-नीची पहाड़ियों, चोटियों व चट्टानी उभारों की शृंखला बन गई हैं। ये पहाड़ियां 300 से 900 मीटर तक हैं, कई कम ऊंची भी हैं जबकि राजस्थान के माउंट आबू पठार पर गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी समुद्र तल से 1,722 मीटर ऊंचाई तक है।हाल ही में अरावली ने पर्यावरण विशेषज्ञों, समाज और मीडिया का ध्यान खींचा जब किसी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा मानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एमओइएफसीसी समिति द्वारा प्रस्तावित स्थानीय तल से 100 मीटर ऊंचाई वाली शर्त मंजूर करते हुए एक फैसला सुनाया जिससे सड़कों पर विरोध और बयानबाज़ी होने लगी।

2024 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अरावली पहाड़ों की एक समान परिभाषा बनाने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत तकनीकी समिति का गठन किया गया, जिसमें समुद्र तल के बजाय स्थानीय तल आधारित राजस्थान की मौजूदा परिभाषा को शामिल किया जा सके। राजस्थान की परिभाषा पर

भरोसा करते हुए, समिति ने मानदंड तैयार किए कि पहाड़ी को अरावली रेंज का हिस्सा मानने के लिए इसकी ऊंचाई आसपास के स्तर से 100 मीटर होनी चाहिए या इसे अरावली श्रृंखला में दो योग्य पहाड़ियों के बीच 500 मीटर दायरे में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर, 2025 को इस परिभाषा को मंजूर कर लिया, जिसका व्यापक विरोध हुआ।सरकार ने इस परिभाषा का बचाव करते हुए इसे मात्र 'तकनीकी' स्पष्टीकरण बताया और कहा कि राजस्थान में यह 2006 से लागू है व इससे अरावली की हर जगह एक जैसी सुरक्षा करने में मदद मिलेगी, जबकि आलोचना के भी यही बिंदु हैं। गत 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक असंतोष का हवाला देकर 20 नवंबर के अपने आदेश पर रोक लगा दी, न कि पहाड़ी की ऊंचाई मापने के यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के मुताबिक। यह क्षेत्र ऐसे भी समुद्र तल से 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा है, यानी यहां के स्थानीय स्थल से 99 मीटर ऊंचा पहाड़ समुद्र तल से 199 मीटर ऊंचा होगा परन्तु टेक्निकल समिति की व्याख्या अनुसार यह पहाड़ अरावली का हिस्सा नहीं माना जायेगा जब तक 100 मीटर ऊंचे दो पहाड़ों के 500 मीटर दायरे में नहीं आएगा। इससे राजस्थान के 90 फीसदी पहाड़ अरावली रेंज से बाहर हो जाएंगे। भारतीय वन सर्वेक्षण मुताबिक, राजस्थान में 12081 अरावली पहाड़ियों में से सिर्फ 1048 (8.7 फीसदी) ही 100 मीटर ऊंचाई का मापदंड पूरा करेंगी।

समुद्र तल एक यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज्ड रेफरेंस पॉइंट है, जबकि लोकल रिलीफ मनमाना है।

दूसरा, राजस्थान में एक परिभाषा है और उसी के अनुसार माइनिंग की अनुमति है, जबकि दिल्ली और हरियाणा में अरावली पहाड़ियों के लिए ऐसी कोई परिभाषा नहीं और माइनिंग पर रोक है।

कमेटी ने राजस्थान लीगल कोड में अरावली को परिभाषित कर 'एक समानता' जोड़ी व इसे हरियाणा और अरावली रेंज साझा करने वाले सभी राज्यों में लागू किया, जिससे कानूनन हरियाणा में भी माइनिंग और अन्य गतिविधियों की अनुमति की राह खुलती है। परिभाषा का घोषित लक्ष्य अरावली में माइनिंग को 'रेगुलेट' करना है, न कि रोकना। दिल्ली और हरियाणा में अरावली में ज्यादा अलग-थलग छोटी पहाड़ियां और चोटियां हैं।

एसडीएम ने पहले नाश्ता कराया, फिर बाजार भेजकर दिलाए गर्म कपड़े

"साहब! ठंड बहुत लग रही है, कंबल दे दो"

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। एडीएम न्यायिक राजेश कुमार की अध्यक्षता में ब्लॉक सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस चल रहा था, एसडीएम संजीव दीक्षित और एसीपी बिल्हौर मंजय सिंह फरियादियों की शिकायतें सुन रहे थे। अधिकारी एक-एक कर समस्याओं के निस्तारण में जुटे थे कि तभी फरियादों की भीड़ के बीच एक ठिठुरता हुआ मासूम चुपचाप सभागार में आ खड़ा हुआ। कांपती आवाज़ में बोला सर जीज ठंड बहुत लग रही है, कंबल दे दो। पल भर के लिए सभागार में सन्नाटा छा गया। प्रशासनिक फाइलों और शिकायतों के बीच इंसानियत ने कुर्सियों से उठकर मासूम को गले लगा लिया।

रामपाटी गांव निवासी करीब 10 वर्षीय यह बच्चा सर्दी से बचने की उम्मीद में ब्लॉक परिसर तक पहुंचा था। बताया गया कि उसे पहले दो दिन बाद तहसील आने को कहा गया था, लेकिन ठंड से बेहाल मासूम सीधे बिल्हौर ब्लॉक में आयोजित समाधान दिवस में अधिकारियों के पास पहुंच गया।

➪ समाधान दिवस में मासूम की पुकार और पिघल गया प्रशासन

➪ कंबल की आस में ब्लॉक मुख्यालय पहुंचा 10 साल का बच्चा

बच्चे की हालत देखते ही एसडीएम डॉ. संजीव दीक्षित ने फाइलें एक तरफ रख दीं। सबसे पहले मासूम को नाश्ता कराया गया। इसके बाद एक कर्मचारी को पैसे देकर बच्चे के साथ बाजार भेजा गया, जहां से उसके लिए नए गर्म कपड़े, स्वेटर और जूते खरीदे गए। इतना ही नहीं, एसडीएम ने स्थानीय लेखपाल को स्पष्ट निर्देश दिए कि बच्चे के घर उसी दिन कंबल पहुंचाया जाए, ताकि उसके परिवार को भी ठंड से राहत मिल सके।

चार शिकायतें निपटीं, बाकी फरियादी आश्वासन लेकर लौटे

- समाधान दिवस में कुल 51 शिकायतें दर्ज की गईं। इनमें से चार शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों में फरियादियों को शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। भूमि विवाद व अवैध कब्जे से जुड़े प्रकरणों में संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों और उपस्थित फरियादियों ने प्रशासन की इस संवेदनशीलता की खुलकर सराहना की। अक्सर संपूर्ण समाधान दिवस केवल शिकायतों की सुनवाई तक सीमित रह जाता है, लेकिन इस बार यह मंच एक मासूम के लिए उम्मीद, राहत और भरोसे की वजह बन गया।

ठंड से कांपता बच्चा जब ब्लॉक पहुंचा था, तब उसके पास सिर्फ़ एक गुहार थी और लौटते वक्त उसके पास गर्म कपड़े, भरा पेट और प्रशासन पर भरोसा था।

मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण तेज

47 बूथ और दो मतदान केंद्र बढ़े

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर) बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान तेज हो गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,बिल्हौर एसडीएम संजीव दीक्षित ने मंगलवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पुनरीक्षण कार्य की जानकारी दी। वहीं 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों के विभाजन पूरा कर लिया गया है। इसके तहत 209-बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र में 2 नए मतदान केंद्र और 47 नए मतदेय स्थल बनाए गए हैं। इसके बाद अब क्षेत्र में कुल 480 मतदेय स्थल हो गए हैं। 6 जनवरी को सभी मतदेय स्थलों पर मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन कराया जाएगा।

➪ राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर पुनरीक्षण की प्रगति बताई गई

अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर चल रहे पुनरीक्षण कार्यक्रम में अब तक 3074 फार्म-6 भरवाए जा चुके हैं। इसके अलावा मतदाता सूची में संशोधन के लिए फार्म-8 और नाम विलोपन के लिए फार्म-7 की सुविधा भी है। विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण में बिना मैपिंग वाले 21,878 मतदाताओं को नोटिस जारी होंगे। यह कार्यवाही 6 जनवरी से 27 फरवरी 2026 तक चलेगी।

सुनवाई स्थलों का निर्धारण कर दिया गया है। इस दौरान तहसीलदार अनुभव चंद्रा, नायब तहसीलदार चंद्र प्रकाश राजपूत, रंजीत यादव, समेत राजनीतिक दल के नेता मौजूद रहे।

पंखे को लेकर विवाद में तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

शिवराजपुर, बिल्हौर (कानपुर)। थाना शिवराजपुर क्षेत्र में पानी के पंखे को लेकर हुए विवाद में युवक के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। पुलिस को दी गई तहरीर के आधार पर ग्राम प्रधान नामक शख्स समेत तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस को संतोष निवासी ग्राम काकूपुर निहाल ने बताया कि 4 जनवरी की शाम वह खेत पर था। इसी दौरान ग्राम तुलापुरवा निवासी आदेश प्रधान ने फोन कर उसे एक आश्रम में बुलाया। वहां आदेश प्रधान और पप्पू मौजूद थे, जहां पप्पू ने उस पर पानी का पंखा खोलने का आरोप लगाया। संतोष ने आरोप से इंकार किया। जब वह गंगापुल के पास पहुंचा तो ग्राम तुलापुरवा निवासी अनुज यादव ने उसे रोककर गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मारपीट में पीड़ित के हाथ और पैर में चोटें आईं। यह मारपीट आदेश प्रधान और पप्पू के कहने पर कराई गई है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आदेश प्रधान, पप्पू और अनुज यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शिवराजपुर इंस्पेक्टर वरुण शर्मा ने बताया कि जांच की जा रही है।

तहसीलदार ने लिया निर्माण कार्य का जायजा

वर्षों से टूटी मकनपुर मेला तहसील बाउंड्री का निर्माण शुरू

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बिल्हौर (कानपुर)। हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार की दरगाह पर बसंत पर्व को लेकर की जा रही तैयारियों के तहत वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ी तहसील मेला बाउंड्री का निर्माण कार्य तहसील प्रशासन द्वारा शुरू करा दिया गया है। इसी क्रम में तहसीलदार अनुभव चंद्रा ने निर्माणाधीन बाउंड्री का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और कार्य की गुणवत्ता को परखा।

निरीक्षण के दौरान तहसीलदार ने उपस्थित ठेकेदार को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि बाउंड्री का निर्माण तय मानकों के अनुरूप किया जाए और कार्य को समय से पूर्ण किया जाए, ताकि मेले के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो। उन्होंने निर्माण कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी।

इसके बाद तहसीलदार ने मेला तहसील परिसर में चल रहे पुताई कार्य का भी जायजा लिया। पुताई में खामियां मिलने पर उन्होंने संबंधित ठेकेदार को मौके पर ही फटकार लगाई और कार्य को गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराने के निर्देश दिए। तहसीलदार ने दो टूक कहा कि सरकारी कार्यों में गुणवत्ता से किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जाएगा। इस दौरान नायब तहसीलदार चंद्र प्रकाश राजपूत, लेखपाल सुनील चौधरी मौजूद रहे ।

बसंत पर्व पर लगता है सरकारी मेला

- हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार की दरगाह पर बसंत पर्व के अवसर पर हर वर्ष भव्य सरकारी मेला आयोजित किया जाता है। इस मेले में दूर-दराज से श्रद्धालु और व्यापारी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मेले को लेकर टेंडर और नीलामी की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली गई है। वहीं विभिन्न विभागों को व्यवस्थाएं समय से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा, साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बाउंड्री निर्माण सहित अन्य कार्यों को तय समय सीमा में पूरा कराने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

डीएम साहब ! कोई नहीं रोक पा रहा जिले में मिट्टी खनन

अवैध खनन का विरोध करना किसान को पड़ा भारी, दबंग माफिया ने परिवार पर किया जानलेवा हमला

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शिवली कोतवाली क्षेत्र के खरगपुर गांव में अवैध खनन का विरोध करना एक किसान परिवार को भारी पड़ गया। दबंग खनन माफियाओं ने किसान और उसके परिवार के साथ गाली-गलौज, मारपीट करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ित किसान बबलू ने माती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपते हुए न्याय की गुहार लगाई है।

पीड़ित किसान बबलू ने बताया कि उसकी जमीन पर दबंग खनन माफिया सोनू तिवारी अपने साथियों अभी ठाकुर,भानु और मयंक के साथ मिलकर जबरन अवैध खनन कर रहे थे। जैसे ही उसे इसकी जानकारी हुई, वह अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंचा और खनन का विरोध किया। खेत में खनन रोकने की बात कहने पर आरोपी आक्रोशित हो गए और गाली-गलौज करने लगे।

आरोप है कि दबंग खनन माफियाओं ने बबलू और उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया। इस दौरान आरोपियों ने जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया और जमकर मारपीट की, जिससे परिवार के कई सदस्य घायल हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने शिवली कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन बबलू का आरोप है कि पुलिस ने सुबह से शाम तक थाने में बैठाए रखा, बावजूद इसके कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस से निराश होकर पीड़ित परिवार सहित बबलू माती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बबलू ने बताया कि मुख्य आरोपी सोनू तिवारी के खिलाफ पहले से करीब एक दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी पुलिस की निष्क्रियता से दबंगों के हौसले बुलंद हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक श्रध्दा नरेंद्र पाण्डेय ने मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय का भरोसा दिलाया है।

यूपी में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के तहत अहम आंकड़े जारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के अंतर्गत निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं से संबंधित महत्वपूर्ण और विस्तृत आंकड़े सार्वजनिक किए हैं। जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रदेश में कुल मतदाताओं में से 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जो कुल मतदाताओं का 81 दशमलव 30 प्रतिशत है।आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 46 लाख 23 हजार मृत मतदाता चिन्हित किए गए हैं, जो कुल मतदाता संख्या का 2 दशमलव 99

प्रतिशत है। वहीं 2 करोड़ 17 लाख मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जो स्थानान्तरित हो चुके हैं अथवा वर्तमान पते पर अनुपस्थित मिले, इनका प्रतिशत 14 दशमलव 06 है।

इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में 25 लाख 47 हजार मतदाता ऐसे पाए गए हैं, जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज हैं। यह संख्या कुल मतदाताओं का 1 दशमलव 65 प्रतिशत है। निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे मतदाताओं का नाम केवल एक ही स्थान पर रखा जाएगा और अन्य स्थानों से नाम हटाया जाएगा।निर्वाचन विभाग के अनुसार स्थानान्तरित अथवा अनुपस्थित मतदाताओं में वे मतदाता शामिल हैं, जो बीएलओ को उपलब्ध नहीं हो सके, जिनके गणना प्रपत्र वापस नहीं मिले या जो अपने पूर्व निवास स्थान से कहीं अन्यत्र स्थायी रूप से स्थानान्तरित हो गए हैं।

इसके अलावा कुछ मतदाता संबंधित मतदान क्षेत्रों में लापता अथवा अनुपस्थित पाए गए या फिर किसी कारणवश 26 दिसंबर 2025 तक गणना प्रपत्र जमा नहीं कर सके।

निर्वाचन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उपरोक्त श्रेणी में शामिल पात्र मतदाता यदि 06 जनवरी 2026 से 06 फरवरी 2026 तक निर्धारित दावा एवं आपत्ति अवधि के दौरान घोषणा पत्र एवं आवश्यक अभिलेखों के साथ संबंधित प्रपत्र भरते हैं, तो उनके नाम मतदाता सूची में पुन: सम्मिलित किए जा सकते हैं।निर्वाचन विभाग ने आम मतदाताओं से अपील की है कि वे इस अवधि में अपने नाम, विवरण एवं स्थिति की जांच अवश्य कर लें, ताकि मतदाता सूची को शुद्ध, अद्यतन और त्रुटिरहित बनाया जा सके।

डिपार्टमेंटल स्टोर में भीषण आग, 15 लाख का सामान जलकर राख, दमकल की दो गाड़ियों ने पाया काबू

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

उन्नाव । उन्नाव जिले में नगर पालिका रोड स्थित डिपार्टमेंटल स्टोर में सोमवार रात करीब 10:30 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने तीन घंटे की कड़ी में मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से करीब 15 लाख का नुकसान हुआ है। सदर कोतवाली के नगर पालिका रोड निवासी मोहम्मद एजाज पालिका के पास में ही डिपार्टमेंटल स्टोर खोले हुए थे। उसमें बकरी के समान के साथ अन्य घरेलू सामानों की बिक्री करते थे। सोमवार रात साढ़े नौ बजे दुकान बंद कर घर चले गए।

रात करीब 10 :30 बजे दुकान के अंदर से धुआं उठाना शुरू हुआ। देखते ही देखते आग की लपटें निकलनी शुरू हो गईं। आसपास रहने वाले लोगों ने दुकानदार को सूचना दी। वह मौके पर पहुंचे और डायल 112 पर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने दमकल को बुलाया। अग्निशमन अधिकारी राममिलन भारती दो गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बाद में मुख्य अग्निशमन अधिकारी भी पहुंच गए। दो टीमें बनाकर आग बुझाना शुरू किया। रात करीब डेढ़ बजे बजे पूरी तरह से आग पर काबू पाया जा सका।इस दौरान आसपास की दुकानदारों की भी धड़कनें तेज रहीं। अचानक से हुई घटना ने दुकानदार मोहम्मद एजाज को तोड़कर रख दिया। इस दौरान उनका ब्लड प्रेशर भी लो होता देख उन्हें वहां से हटा दिया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह बताया कि अभी तक शॉर्ट सर्किट से ही आग लगने की संभावना है। दो गाड़ियों से आग पर काबू पा लिया गया था। पानी कम पड़ने पर पास की ही एक फैक्टरी से गाड़ी में पानी भरवाया गया था। आग से पूरा डिपार्टमेंटल स्टोर जल गया है। आसपास की दुकानें सुरक्षित हैं।

अब नए मतदाताओं को बढ़ाने पर दिया जाएगा जोर

एसडीएम सर्वेश सिंह ने मतदाता संबंधी कार्यों के लिए की सभी कार्मिकों की सराहना

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशन के बाद नए मतदाताओं को जोड़ने का कार्य युद्धस्तर पर शुरू किया जाएगा। भारतीय लोकतंत्र में प्रावधान है कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति वोट डाल सकता है। इसके लिए जरूरी है कि फॉर्म 6 बीएलओ से भरवाकर या ऑनलाइन करके अपना वोट बढ़वाना सुनिश्चित करें।1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले लोग फॉर्म 6 भरकर अपना वोट बनवायें। यह बात एसडीएम सर्वेश सिंह ने मतदाता सूची प्रकाशन पहले कही।

मंगलवार को रसूलाबाद तहसील सभागार में उपजिलाधिकारी सर्वेश सिंह,तहसीलदार संतोष कुमार ने वृहद मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद नए वोट बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं इस बार 246 से बढ़कर अब 256 बूथ हो गए। इस बार ग्रामीण क्षेत्र में बूथों की संख्या बढ़ गई है। वहीं इसके बाद आरपीएस इंटर कॉलेज में मतदाता जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। जहां छात्राओं व शिक्षकों को उपजिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ निर्धारित समय तक दावा व आपत्तियां ली जाएंगी। इसके साथ ही नए मतदाताओं को बढ़ाने का कार्य होगा। वहीं इस दौरान तहसीलदार संतोष कुमार ने बताया की क्षेत्र के इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज में एक कक्ष मतदाता पंजीकरण का बनाया जा रहा है। जहां नए मतदाताओं को बढ़ाने का कार्य किया जाएगा। जो मतदाता एक स्थान पर हैं अपना स्थान परिवर्तन करना चाह रहे हैं वह फॉर्म 8 भरकर स्थान बदल सकते हैं। इस मौके पर नायब तहसीलदार हरिशंकर वर्मा, प्रधानाचार्य डीपी शुक्ला, कानून गो अनिल कुमार, कुंवर सिंह, जितेंद्र त्रिपाठी, उप प्रधानाचार्य अजय पाल यादव, दुर्गेश त्रिपाठी, राजीव शुक्ला,बंगाली बाबू शुक्ला,अवधेश पाल ,विश्वनाथ कुशवाहा ,लेखपाल रावेन्द्र कुमार बृजेंद्र सविता, सुरेश सिंह यादव, शिशुपाल, रामगोपाल, राजकुमार श्रीवास्तव, विनीत द्विवेदी, वीरेंद्र कुमार, संजीव गुप्ता, ओमकार शुक्ला, बीएलओ मीना मिश्रा, कंचन पाल, शैलजा मिश्रा सहित कई शिक्षक मौजूद रहे।

मिशन शक्ति : पुलिस ने महिलाओं को दिए सुरक्षा के टिप्स

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

एसपी श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के निर्देशन में बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर चला अभियान

कानपुर देहात। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है।पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के कुशल मार्गदर्शन में जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 'मिशन शक्ति 5.0' के तहत विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस टीमों ने बाजारों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थानों पर जाकर महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया।

जागरूकता कार्यक्रम के दौरान महिला पुलिसकर्मियों ने बालिकाओं को मुसीबत के समय तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। उन्हें बताया गया कि किसी भी आपात स्थिति में वे 1090 (महिला शक्ति लाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112 (इमरजेंसी नंबर) और 1076 (मुख्यमंत्री हेल्पलाइन) पर बेझिझक कॉल कर सकती हैं। पुलिस ने इन नंबरों के प्रभावी उपयोग के बारे में विस्तार से समझाया।

साथ ही महिलाओं को न केवल शारीरिक

सुरक्षा बल्कि डिजिटल सुरक्षा के प्रति भी सचेत किया गया। पुलिस ने साइबर स्टॉकिंग, फिशिंग और सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी से होने वाले खतरों से बचने के टिप्स साझा किए। इसके साथ ही, महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों जैसे पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम और आईटी एक्ट के बारे में जानकारी प्रदान की गई, ताकि वे शोषण के विरुद्ध आवाज उठा सकें।

यूपीकॉप एप से मिलेगा पुलिस सेवाओं का लाभ

पुलिस अधिकारियों ने महिलाओं को 'यूपीकॉप' मोबाइल एप डाउनलोड करने की सलाह दी,

जिससे वे घर बैठे एफआईआर दर्ज करने, चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने और अन्य पुलिस सेवाओं का लाभ उठा सकें। अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करना और उन्हें समाज में सुरक्षित महसूस कराना है।

इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और छात्राओं ने पुलिस की इस पहल की सराहना की।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादक: अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 । Email: swarajindia2023@gmail.com । Mob: 7800009853, । Website: www.swarajindianews.com । (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे) प्रादेशिक कार्यालय :4ए/5,119/10बी, खान बिल्डिंग, पार्क रोड हजरतगंज

विष्णु महायज्ञ: भक्तिभाव में डूबी महिलाएं सिर पर कलश लेकर चलीं

तिंगाई गांव में हुआ भव्य आयोजन, उमड़ा जनसैलाब

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। रूरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत तिगाई गांव में 67वें वार्षिकोत्सव एवं 29वें विष्णु महायज्ञ का शुभारंभ अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ किया गया। महायज्ञ के प्रथम दिवस विशाल कलश एवं जल यात्रा का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें गांव सहित आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने बढ़-चढ़कर सहभागिता की।

कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर चलती नजर आईं, वहीं पुरुष और युवा वर्ग भी पूरे उत्साह के साथ यात्रा में शामिल रहा। पूरे गांव में डीजे बाजे की गूंज और धार्मिक भजनों के मधुर स्वर से वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। गांव की गलियों में जयघोष और भक्ति गीतों के साथ निकली यात्रा ने लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया।

द्वितीय दिवस में प्रभु ब्रह्मदेव बाबा की कृपा से भागवत महाकथा का शुभारंभ किया गया। कथा के प्रथम दिवस कथा वाचक अरविन्द कुमार की पावन वाणी से भागवत कथा का रसपान कराया गया। कथा के दौरान धर्म, भक्ति और मानव जीवन के मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भावविभोर हो उठे।

कथा स्थल पर दूर-दराज से आए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। पूरे आयोजन में शांति, अनुशासन और धार्मिक सौहार्द का विशेष ध्यान रखा गया। आयोजन समिति द्वारा सभी ग्राम व क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया गया है कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर भागवत महाकथा एवं महायज्ञ का पुण्य लाभ प्राप्त करें।

पूरा गांव इन दिनों धार्मिक रंग में रंगा हुआ है और हर ओर आस्था, भक्ति और उत्सव का माहौल बना हुआ है।

सड़क के गड्ढे बन रहे हादसे का सबब

» **जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी से ग्रामीणों का जीना हुआ मुहाल**

» **बेला-चौबेपुर संपर्क मार्ग से सुजानपुर जाने वाले मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे**

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों की अनदेखी और उदासीनता ग्रामीणों के लिए मुसीबत का सबक बन रही है।

बेला-चौबेपुर संपर्क मार्ग से सुजानपुर हीकेपुर जाने वाले मार्ग की दुर्दशा हो गई है। जहां पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। बावजूद इसके जिम्मेदारों ने सुध नहीं ली। रसूलाबाद विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत सुजानपुर, केवलेपुर, हीकेपुर सहित दर्जनों गांव के लोगों के लिए बेला-चौबेपुर संपर्क मार्ग पर जाना मुश्किल हो रहा है। उक्त मार्ग वर्षों से बड़े-बड़े गड्ढे हैं। जिन पर चलना अब दूभर हो गया है। कई बार स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि सहित अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन समस्या जस की तस है। यहां के रहने वाले धीरज यादव ने बताया कि उक्त गांव से अन्य गांव भी जुड़े हुए हैं। जो इस रास्ते से जिला मुख्यालय माती सहित कानपुर शहर के लिए गुजरते हैं। एक लंबा अरसा हो गया लेकिन न तो मार्ग का मरम्मतीकरण हुआ और न ही दोबारा डामरीकरण हुआ। वहीं पूर्व प्रधान अनिरुद्ध सिंह राजावत मुन्ना ने बताया कि गांव के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। विकास कार्यों में गांव पिछड़ता जा रहा है। वहीं उक्त संदर्भ में जब लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता से बात करना चाही तो उनका फोन नहीं उठा।

झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की हुई थी हत्या, प्रेमी फरार

फरार आरोपी पर 25 हजार का इनाम, बेटे और बहनोई की भूमिका भी जांच के घेरे में

»स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

झांसी। झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की नृशंस हत्या ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि अनीता की गोली मारकर हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके पूर्व प्रेमी मुकेश झा ने की थी। वारदात को सड़क हादसा दिखाने के लिए आरोपी ने ऑटो पलट दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुकेश झा पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।

FOLLOW UP

अनीता नवाबाद थाना क्षेत्र के तालपुरा स्थित अंबेडकर नगर में रहती थीं। वह तीन बच्चों की मां थीं। करीब नौ साल पहले वह भगवंतपुरा के पास स्थित एक ग्लास फैक्ट्री में काम करती थीं, जहां मुकेश झा मैनेजर था।

यहीं दोनों की दोस्ती हुई, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। यह रिश्ता करीब सात साल तक चला। बाद में अनीता ने नौकरी छोड़ दी और ऑटो चलाकर परिवार का पालन-पोषण करने लगीं।पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ समय से मुकेश अनीता के साथ मारपीट करने लगा था, जिससे परेशान होकर अनीता ने करीब पांच महीने पहले उससे रिश्ता तोड़ लिया। बीते रविवार रात करीब साढ़े नौ बजे अनीता घर से ऑटो लेकर निकली थीं। स्टेशन रोड पर सुकुवां-ढुकवां कॉलोनी के पास मुकेश ने पहले उनसे झगड़ा किया और फिर कनपटी पर गोली मार दी।

सोमवार को हुए पोस्टमॉर्टम में पुष्टि हुई कि अनीता की मौत गोली लगने से हुई थी। गोली सिर से होकर गले में फंस गई थी। पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। अनीता के गहने भी मौके से गायब मिले, जिससे लूट की आशंका भी सामने आई है। पुलिस ने अनीता के पति की तहरीर पर मुकेश झा, उसके बेटे शिवम झा और बहनोई मनोज झा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को शक है कि वारदात में मुकेश के साथ उसके करीबी भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल मुख्य आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।

नववर्ष पर डीजीपी आवास में शानदार डिनर

» सौहार्द्रपूर्ण रात्रि भोज में अफसरों ने परिवार संग बिताए यादगार पल

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। नववर्ष के अवसर पर डीजीपी राजीव कृष्णा के आवास पर गत रात आत्मीय और उल्लासपूर्ण वातावरण देखने को मिला। रात्रि भोज में आईएएस और आईपीएस अधिकारी अपने परिवारों के साथ शामिल हुए और हल्के-फुल्के माहौल में आपसी मेलजोल के साथ समय बिताया।

डीजीपी राजीव कृष्णा और उनकी पत्नी आईआरएस अधिकारी मीनाक्षी सिंह ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया और स्नेहपूर्ण आतिथ्य से आयोजन को यादगार बना दिया। कड़ाके की ठंड के बीच आवास के लॉन में अलाव की व्यवस्था की गई, जिससे सर्दी का असर महसूस नहीं हुआ और वातावरण और भी सुखद बन गया।कार्यक्रम में प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद के साथ आईएएस अधिकारी डॉ हरिओम और उनकी पत्नी मालविका की उपस्थिति ने महफिल में विशेष रंग भर दिया। कला प्रेमी डॉ हरिओम और मालविका गीत, ग़ज़ल और कविताओं के प्रति अपने अनुराग के लिए जाने जाते हैं,

जिससे बातचीत और भी रोचक हो गई।इस रात्रि भोज में आईपीएस अधिकारी नवीन अरोरा, मोहित अग्रवाल और प्रवीण कुमार भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया और नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ सौहार्द और सकारात्मक ऊर्जा के साथ नए साल का स्वागत किया।

लोकनृत्य साधिका संगम लता को 'अयोध्या गौरव सम्मान'

अयोध्या महोत्सव के समापन अवसर पर दिया गया सम्मान

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या।अवध की लोकसंस्कृति को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाली लोकनृत्य कलाकार संगम लता को इस वर्ष 'अयोध्या गौरव सम्मान' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें अवध के पारंपरिक एवं लोकप्रिय बधावा लोक नृत्य को सहेजने, संवारने और मंचों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदान किया गया।यह सम्मान बहुचर्चित अयोध्या महोत्सव के समापन अवसर पर दिया गया। महोत्सव का शुभारंभ 25 दिसंबर को सहादतगंज स्थित एक निजी संस्थान में दुखदुरियां पूजन के साथ हुआ था। आयोजक हरीश श्रीवास्तव ने बताया कि अयोध्या महोत्सव पिछले 17 वर्षों से निरंतर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अवधी के साथ-साथ भोजपुरी लोकसंस्कृति के कलाकार विभिन्न दिनों में अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। सभी प्रतिभागी कलाकारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है, जबकि संपूर्ण महोत्सव में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकार को अयोध्या गौरव सम्मान प्रदान किया जाता है।गौरतलब है कि संगम लता को इससे पूर्व भी लोकनृत्य के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित सम्मान मिल चुके हैं। बधावा लोक नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए उन्हें नोएडा में आयोजित ट्रेड शो में सम्मानित किया गया था। इसके अलावा महाकुंभ में उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। अयोध्या गौरव सम्मान मिलने पर संगम लता ने इसे अवध की लोकपरंपरा और गुरुजनों को समर्पित बताते हुए कहा कि यह सम्मान लोकसंस्कृति को आगे बढ़ाने के उनके संकल्प को और मजबूत करेगा।

20 हजार जरूरतमंदों को कंबल, मेधावियों को साइकिल और बालिकाओं को दी सिलाई मशीन

स्व. प्रभात सिंह की पुण्यतिथि पर मड़ना गांव में सामाजिक आयोजन

»स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या।पूरा बाजार क्षेत्र की ग्राम सभा मड़ना में स्वर्गीय प्रभात सिंह की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मानवता, सेवा और शिक्षा को समर्पित इस आयोजन ने पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर दिया। ब्लॉक प्रमुख उषा सिंह, उनके पुत्र शिवेंद्र सिंह (प्रमुख संघ जिलाध्यक्ष) और दीपेंद्र सिंह (गन्ना समिति अध्यक्ष) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 20 हजार जरूरतमंद, असहाय और निराश्रित लोगों को निशुल्क कंबल वितरित किए गए। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच यह पहल गरीबों के लिए बड़ी राहत साबित हुई।

कार्यक्रम में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकासखंड पूरा की 54 ग्राम सभाओं के 100 मेधावी छात्रों को साइकिल देकर सम्मानित किया गया, ताकि संसाधनों की कमी उनकी पढ़ाई में बाधा न बने। वहीं 30 जरूरतमंद बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीनें वितरित की गईं।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जरूरतमंदों, दिव्यांगों और निराश्रितों की सेवा ही सच्ची मानवता है। समाज के सक्षम लोगों को आगे आकर ऐसे कार्यों में योगदान देना चाहिए।ब्लॉक प्रमुख उषा सिंह ने कहा कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज के प्रति दायित्व का प्रतीक है। स्वर्गीय प्रभात सिंह का सपना था कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले, जिसे यह आयोजन साकार कर रहा है।

आयोजन समिति के अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने सभी अतिथियों और सहयोगियों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक सोच और बदलाव की मजबूत नींव रखते हैं। दीपेंद्र सिंह ने इसे संघर्षरत लोगों के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व सांसद विनय कटिहार, विधायक वेद प्रकाश गुप्त, गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, बीकापुर विधायक डॉ. अमित सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, महिला मोर्चा महानगर मंत्री स्वाति सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शंभूनाथ सिंह 'दीपू', पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, शिक्षक नेता विश्वनाथ सिंह, अवधेश पांडे 'बदल' सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, संत-महात्मा और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

अवैध खनन ने डुबोया खान निरीक्षक निलंबित

अयोध्या में बालू माफिया-अफसर गठजोड़ पर गिरी बड़ी गाज

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या।अयोध्या में घाघरा नदी के सीने को छलनी कर रहे अवैध बालू खनन पर स्वराज इंडिया की पड़ताल का बड़ा असर सामने आया है। खबर प्रकाशित होने के बाद शासन स्तर पर हुई जांच में चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए, जिसके बाद खान निरीक्षक पाठक चन्द्रशेखर रामानुज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा कराए गए भौतिक निरीक्षण और अभिलेखीय जांच में साफ हो गया कि सोहावल तहसील के फतेहपुर सरैया गांव में स्वीकृत खनन पट्टा नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा था।

हलचल खबर का असर

मशीनों से नदी की धारा में खनन, पट्टा क्षेत्र के बाहर बालू की खुदाई, ओवरलोड ट्रकों का संचालन और सीसीटीवी व सीमा स्तंभों का न होना सब कुछ जांच में दर्ज मिला।

जांच रिपोर्ट के अनुसार कांटे के आगे खड़े ट्रक यूपी 03 एटी 7602 में 30 घन मीटर बालू लदी थी, जबकि ई-एमएम मात्र 14 घन मीटर का जारी था। यानी 16 घन मीटर बालू का अवैध परिवहन। इतना ही नहीं, कांटे से पहले भी 2ङ्क3 ओवरलोड ट्रक खड़े मिले। जांच में यह भी सामने आया कि खनन पट्टा क्षेत्र में 360 डिग्री सीसीटीवी कैमरा तक नहीं लगाया गया, जबकि यह अनिवार्य था। पट्टा पिलर भी नदारद मिले।

सबसे सनसनीखेज खुलासा तब हुआ जब क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी ने जांच के दौरान जानलेवा हमले की बात दर्ज कराई। औद्योगिक क्षेत्र में 15-17 लोगों ने अधिकारी से मारपीट की, सरकारी दस्तावेज फाड़े गए और गाली-गलौज की गई।

हैरानी की बात यह रही कि मौके पर मौजूद खान निरीक्षक पाठक चन्द्रशेखर रामानुज ने न तो बीच-बचाव किया, न ही हमलावरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई कराई जबकि वे हमलावरों को पहचानते थे। यह चुप्पी ही उनके निलंबन की सबसे बड़ी वजह बनी।

जांच में स्पष्ट कहा गया है कि वर्ष 2023 से अयोध्या में तैनात खान निरीक्षक ने अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी अंकुश नहीं लगाया। यह उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 का सीधा उल्लंघन है। इसी के चलते उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच अधिकारी बरेली के क्षेत्रीय प्रवर्तन अधिकारी अजय कुमार यादव को बनाया गया है।

हालांकि खान निरीक्षक के निलंबन से सवाल खत्म नहीं होते।

क्या इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन सिर्फ एक अफसर की लापरवाही थी? या फिर बालू माफिया को सिस्टम के भीतर से खुला संरक्षण मिला हुआ था? स्वराज इंडिया की खबर ने परतें खोली हैं, लेकिन असली परीक्षा अब आगे है क्या बालू माफिया तक भी कार्रवाई पहुंचेगी, या कहानी फिर किसी फाइल में दफन कर दी जाएगी?

किशोरी हत्याकांड का खुलासा, प्रेमी गिरफ्तार

» अवैध संबंधों को लेकर उपजा शक बना हत्या का कारण

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या ।कोतवाली नगर पुलिस ने किशोरी की सनसनीखेज हत्या का सफल खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध संबंध और शक के चलते की गई इस नृशंस हत्या का आरोपी मृतका का प्रेमी निकला, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है।

पुलिस के अनुसार 3 जनवरी को जीआईसी फ्लाईओवर के नीचे रेलवे लाइन किनारे किशोरी की सुनियोजित तरीके से हत्या की गई थी। आरोपी ने पहले किशोरी को बहाने से झाड़ियों की ओर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया ।मृतका बेगमगंज मकबरा क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली नगर प्रभारी अश्विनी कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राम प्रवेश सोनी को रेलवे स्टेशन रोड से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मृतका का एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किया है। पूछताछ में आरोपी ने अवैध संबंधों को लेकर उपजे शक को हत्या का कारण बताया।

मृतका के परिजनों पर एफआईआर डॉक्टर बनौधा ने जताया दुख

निर्मला हॉस्पिटल प्रकरण में नया मोड़

» अस्पताल में तोड़फोड़, आग लगाने के प्रयास और कर्मचारियों से मारपीट के आरोप

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

अयोध्या।इंजेक्शन के कथित ओवरडोज से महिला की मौत के मामले में अब विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। निर्मला हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. आर.के. बनौधा की तहरीर पर कोतवाली अयोध्या पुलिस ने मृतका के बेटों सहित 20-25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में अस्पताल में तोड़फोड़, आग लगाने के प्रयास और कर्मचारियों के साथ मारपीट के आरोप लगाए गए हैं।

डॉ. बनौधा ने इस पूरे घटनाक्रम पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान का उद्देश्य किसी भी पीड़ित परिवार को आघात या तकलीफ पहुंचाना नहीं है। मृतका के परिजनों के प्रति उनकी पूरी संवेदना है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि मौत के असली कारण की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन परिजनों से अपील है कि जांच पूरी होने तक संयम रखें। लगातार लगाए जा रहे आरोपों से अस्पताल की छवि को भारी नुकसान पहुंचा है।

दर्ज एफआईआर के अनुसार, 16 दिसंबर को एक महिला मरीज की मौत लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल में हो गई थी, जो पहले निर्मला हॉस्पिटल में भर्ती थी। उसी रात मृतका के परिजन सुशील कौशल, सुनील कौशल और 25-30 अज्ञात लोगों के साथ अस्पताल पहुंचे और तोड़फोड़, कर्मचारियों से मारपीट तथा आग लगाने की कोशिश की।

इसके अलावा 19 दिसंबर की शाम करीब आठ बजे अस्पताल की कर्मचारी चित्रा सोनकर और रानी साहबगंज से अस्पताल आ रही थीं। साकेतपुरीङ्गशाहजहांपुर मोड़ पर काली गाड़ी में सवार सुशील कौशल, उसके भाई व अन्य लोगों ने उन्हें रोककर नाम पूछा और कथित तौर पर जातिसूचक गालियां देते हुए मारपीट की। कोतवाल अयोध्या पंकज सिंह ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

मीडिया कर्मियों से बदसलूकी पर मांगी माफी

निर्मला हॉस्पिटल के कर्मचारियों द्वारा एक मीडिया कर्मी से बदसलूकी के मामले में अस्पताल प्रबंधन ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। डॉ. आर.के. बनौधा ने पहले संबंधित पत्रकार से व्यक्तिगत मुलाकात की, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए संस्थान ठोस कदम उठाएगा।

लेबनान पर फिर इस्राइल का जोरदार हवाई हमला

हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण पर सरकारी बैठक से पहले बढ़ा सैन्य तनाव

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

नई दिल्ली। इस्राइल की वायुसेना ने मंगलवार तड़के लेबनान के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में कई ठिकानों पर जोरदार हवाई हमले किए। इन हमलों की चपेट में लेबनान का तीसरा सबसे बड़ा शहर सीदोन भी आया, जहां रात करीब एक बजे एक तीन मंजिला व्यावसायिक इमारत पूरी तरह ध्वस्त हो गई। यह इलाका वर्कशॉप और मैकेनिक की दुकानों वाला व्यावसायिक क्षेत्र था, जहां किसी के रहने की जानकारी नहीं थी।

घटनास्थल पर मौजूद एसोसिएटेड प्रेस के फोटोग्राफर के मुताबिक, हमले के बाद कम से कम एक व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। राहत और बचाव दल मलबे में अन्य लोगों की तलाश में जुटे हैं, हालांकि अब तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। सीदोन पर किया गया यह हमला बिना किसी पूर्व चेतावनी के हुआ, जिस पर इस्राइली सेना की ओर से तत्काल कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया।

इससे एक दिन पहले सोमवार को भी इस्राइली सेना ने दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में कई ठिकानों को निशाना बनाया था। इस्राइल का दावा है कि इन इलाकों में हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों का बुनियादी ढांचा मौजूद है। हमलों से पहले इस्राइली सैन्य प्रवक्ता अविचाई अद्राई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतावनी जारी कर पूर्वी बेका घाटी और दक्षिणी लेबनान के कुछ गांवों को खाली करने को कहा था।

➪ सीदोन में तीन मंजिला इमारत ध्वस्त, दक्षिणी और पूर्वी इलाकों पर एक साथ हमले

लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, बेका घाटी के मनारा गांव में जिस घर पर हमला हुआ, वह हमास के सैन्य कमांडर शरहाबिल अल-सैयद का था, जो मई 2024 में इस्राइली ड्रोन हमले में मारा गया था। चेतावनी के बाद इलाकों को खाली करा लिया गया था, इसलिए इन हमलों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि, सोमवार सुबह दक्षिणी गांव ब्राईकेह में एक कार पर हुए ड्रोन हमले में दो लोग घायल हो गए थे, जिन्हें इस्राइल ने हिजबुल्लाह के सदस्य बताया है।

यह सैन्य कार्रवाई ऐसे समय में हुई है, जब लेबनानी सरकार हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण पर अहम कदम उठाने की तैयारी कर रही है। लेबनानी सेना पिछले साल से फिलिस्तीनी समूहों के हथियार जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है और सरकार का दावा है कि 2025 के अंत तक इस्राइल सीमा से सटे सभी इलाके हिजबुल्लाह की सशस्त्र मौजूदगी से मुक्त कर दिए जाएंगे। इसी कड़ी में गुरुवार को होने वाली सरकारी बैठक में सेना प्रमुख जनरल रुडोल्फ हायकल भी शामिल होंगे। लगातार हो रहे हवाई हमलों ने इस पूरी प्रक्रिया से पहले क्षेत्र में तनाव को और बढ़ा दिया है।

खाकी की गुंडई 20 लाख वसूले

छह पुलिसकर्मियों पर FIR

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

बांदा। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में पुलिस की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। युवक को अगवा कर 20 लाख रुपये वसूलने और फिर उसे गांजा तस्करी के फर्जी मामले में जेल भेजने के सनसनीखेज प्रकरण में अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। सोमवार को विशेष न्यायाधीश (डकैती) की अदालत ने अतर्रा के तत्कालीन थानाध्यक्ष, एक उपनिरीक्षक, चार सिपाहियों और एक मुखबिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

यह मामला बबेरू कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव निवासी कमालुद्दीन पुत्र हाजी ताहिर से जुड़ा है। पीड़ित के अनुसार, मामले में कहीं सुनवाई न होने पर उसने 25 अप्रैल 2025 को अदालत की शरण ली थी। कोर्ट द्वारा रिपोर्ट तलब किए जाने पर अतर्रा थाने से फर्जी रिपोर्ट भेजी गई, जिसके आधार पर वाद खारिज कर दिया गया। इसके बाद पीड़ित ने उच्चाधिकारियों और मानवाधिकार आयोग में शिकायत की।

मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ने तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र और नरैनी सीओ अंबुजा त्रिवेदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की। एसआईटी की

➪ एसआईटी जांच में दोषी पाए गए तत्कालीन थानाध्यक्ष, एसआई, चार सिपाही और मुखबिर

➪ युवक को अगवा कर 20 लाख रुपये वसूलन, गांजा तस्करी के मामले में जेल भेजा था

जांच में तत्कालीन थानाध्यक्ष समेत सभी सात आरोपी दोषी पाए गए।

जांच रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित ने 3 अक्टूबर 2025 को फिर थाना और एसपी से कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई कदम नहीं उठाया गया। आखिरकार पीड़ित ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गगन कुमार भारती ने अतर्रा थानाध्यक्ष को आदेश दिया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष अरविंद सिंह, एसआई सुधीर कुमार चौरसिया, हेड कांस्टेबल महेश्वर प्रसाद, सिपाही अंकित वर्मा, अरमान अली, अखिलेश और मुखबिर खास बउवा के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जाए। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और पूरे मामले को कानून व्यवस्था पर बड़ा धब्बा माना जा रहा

लखनऊ-कानपुर समेत बड़े कारोबारियों पर पड़े छापों में रिश्वत के खेल की तलाश

सीबीआई ने झांसी जीएसटी रिश्वत कांड में बढ़ाया जांच का दायरा

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

झांसी। झांसी में डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी से जुड़े जीएसटी रिश्वत प्रकरण में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। अब सीबीआई पिछले चार वर्षों में जीएसटी और सीजीएसटी के तहत बड़े कारोबारियों के यहां पड़ी छापेमारियों से जुड़ी फाइलों की गहन पड़ताल करेगी। इन छापों के दौरान जब्त दस्तावेजों, की गई कार्रवाई और उसके बाद हुए फैसलों की भी जांच की जाएगी।

सीबीआई को यह अहम जानकारी विभाग के कुछ अफसरों-कर्मचारियों के बयान और छापों से परेशान व्यापारियों से मिली है। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि छापेमारी के बाद भी रिश्वत का खेल चलता रहा और इसमें पहले तैनात रहे कई अफसर व कर्मचारी

➪ अफसरों-कर्मचारियों के रैकेट के संकेत, कई और नाम सीबीआई के रडार पर आए

शामिल थे। इन्हीं तथ्यों के आधार पर सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले में झांसी की डिप्टी कमिश्नर प्रभा भंडारी, सुपरवाइजर अनिल तिवारी, अजय शर्मा, वकील नरेश गुप्ता और जय दुर्गा हार्डवेयर के संचालक राजू मंगतानी को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के ठिकानों से भारी मात्रा में नकदी, जेवर और संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज बरामद होने के बाद मामला और गंभीर हो गया।

जांच के दौरान जब सीबीआई ने विभागीय

कर्मचारियों के बयान दर्ज किए तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। बताया गया कि वर्ष 2022 से 2025 के बीच लखनऊ, कानपुर और अन्य शहरों में पड़े बड़े जीएसटी छापों के दौरान भी कुछ अफसरों और कर्मचारियों ने कथित तौर पर नियमों की आड़ में अवैध वसूली का खेल खेला। इन छापों से जुड़ी फाइलों में ही अब सीबीआई इन आरोपों की सच्चाई तलाशेगी। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक, झांसी जीएसटी प्रकरण में सिर्फ कुछ नाम नहीं बल्कि अफसरों और कर्मचारियों का एक पूरा रैकेट सक्रिय था, जो रिश्वतखोरी में एक-दूसरे का साथ दे रहा था। इस नेटवर्क से जुड़े कई और लोग अब जांच एजेंसी के रडार पर हैं और आने वाले दिनों में कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है।